



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 20-2023] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 16, 2023 (VAISAKHA 26, 1945 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2023

संख्या 1/20/2016-5पी0आर0 (एफ0डी0).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2023, कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम प्रथम जनवरी, 2016 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8 में, उपनियम (क) में, खण्ड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(7) सरकारी कर्मचारी के संबंध में “वृत्तिमूलक स्तर या वृत्तिमूलक वेतन ढांचा” से अभिप्राय है, उस द्वारा धारित पद के लिए विहित वेतन मैट्रिक्स में वृत्तिमूलक स्तर। इसमें प्रथम जनवरी, 2016 के बाद पद का संशोधित वृत्तिमूलक स्तर शामिल हैं, किन्तु इसका अभिप्राय कोई अन्य स्तर नहीं है, जिसमें सरकारी कर्मचारी किसी अन्य न्यायोचित्य जैसे सेवाकाल या उच्चतर/अतिरिक्त योग्यता से उसे वैयक्तिक उपाय के रूप में अपना वेतन प्राप्त कर रहा है।”।
- उक्त नियमों में, नियम 27 में, उपनियम (3) का लोप कर दिया जाएगा।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**FINANCE DEPARTMENT****Notification**

The 11th May, 2023

No.1/20/2016-5PR(FD).- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Civil Services (Pay) Amendment Rules, 2023.
(2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 2016.
2. In the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016 (hereinafter called the said rules), in rule 8, in sub-rule (a), for clause (7), the following clause shall be substituted, namely:-

“(7) “functional level or functional pay structure” in relation to a Government employee means the functional level in pay matrix prescribed for the post held by him. It includes modified functional level after 1st January 2016 of a post, but does not mean any other level in which the Government employee is drawing his pay as a measure personal to him with any other justification like length of service, or higher/ additional qualification.”.
3. In the said rules, in rule 27, sub-rule (3) shall be omitted.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.